बहुजन हिताय! सक्षम भारत बहुजन सुखाय!

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 256 ● नई दिल्ली ● वीरवार 30 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

छात्रों पर कार्रवाई का मामला: पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर कोर्ट का निर्देश

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की शिकायत को आज शाम पांच बजे तक केस डायरी में दर्ज करें। यह शिकायत छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने 23 जुलाई को शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की डायरी संख्या (डायरी नंबर) या रसीद नहीं मिली थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि तकनीकी खराबी (टेक्निकल गड़बड़ी) के कारण डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं हो सकी।

एफआरएस ने खोली प्रदर्शन में शामिल अपराधियों की कुंडली, संगीन जुर्म के आरोपी भी दिखे

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) ने जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान 2873 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान की है। हालांकि, जांच में सामने आया है कि मौजूदा समय में एफआरएस की चेहरे पहचानने की क्षमता करीब 15 से 20 प्रतिशत के बीच है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सिस्टम ने प्रदर्शन में मौजूद अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के केवल एक हिस्से की ही पहचान की होगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एफआरएस की सटीकता कई तकनीकी पहलुओं पर निर्भर करती है। इसमें कैमरे की गुणवत्ता, रोशनी की स्थिति, चेहरे का कोण और इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम की भूमिका अहम होती है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2018 में एक अदालत में स्वीकार किया था कि उस समय इस्तेमाल किए जा रहे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की सटीकता दर करीब एक प्रतिशत थी। कई बार सिस्टम उम्र और लिंग पहचानने में भी गलती करता था।

हालांकि, समय के साथ तकनीक को अपडेट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की पहचान नियंत्रित माहौल में, जैसे एयरपोर्ट या कार्यालय में स्थिर कैमरे के सामने की जाए तो आधुनिक एफआरएस सिस्टम काफी अधिक सटीक परिणाम दे सकते हैं। लेकिन भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रदर्शनों या कम रोशनी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज से पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता है। एफआरएस जांच में सामने आया कि पहचाने गए 2873 लोगों में से 989 का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें हत्या के मामलों में शामिल 101 आरोपी, हत्या के प्रयास के 62 आरोपी और डकैती व लूट के मामलों में शामिल 284 लोग शामिल हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के 61 आरोपी, पॉक्सो एक्ट के छह आरोपी और महिलाओं से छेड़छाड़ के 25 आरोपी भी मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल कुछ आरोपी पहले भी गंभीर मामलों में संलिप्त रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में शामिल आठ आरोपी ऐसे थे, जिनके खिलाफ दो या उससे अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हथियार अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल 229, झपटमारी के 135, अपहरण के 19 और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े 67 आरोपी भी एफआरएस के जरिए चिन्हित किए गए। हत्या के मामलों में शामिल आरोपियों में 142 ऐसे मिले जिनकी दो या उससे अधिक मामलों में संलिप्तता रही, जबकि 12 आरोपी ऐसे थे जिनके खिलाफ 10 या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लूट और डकैती के मामलों में भी कई पुराने अपराधी सामने आए। इनमें 155 आरोपी ऐसे थे जो दो या उससे अधिक मामलों में शामिल रहे, जबकि 31 आरोपियों के खिलाफ 10 या उससे अधिक मामले दर्ज थे। एनडीपीएस मामलों में भी नौ आरोपी ऐसे मिले, जिनकी दो या उससे अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्तता रही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एफआरएस का उद्देश्य भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति को अपराधी घोषित करना नहीं, बल्कि पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले संदिग्धों की पहचान कर जांच में सहायता करना है।

राज्यसभा से 'वंदे मातरम विधेयक पारित, अब राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर क्या सजा होगी?

नई दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालना अब आपराधिक अपराध माना जाएगा। यह विधेयक विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पारित हुआ। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में उठाया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के दायरे का विस्तार करता है। अभी तक इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान 'जन गण मन' को कानूनी संरक्षण प्राप्त था। अब इसमें राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी शामिल कर लिया गया है। विधेयक ऐसे सभी कृत्यों को दंडनीय बनाता है, जिनमें जानबूझकर 'वंदे मातरम' के गायन को रोकना, बाधित करना या उसका अपमान करना शामिल हो। विधेयक ऐसे समय पारित हुआ है, जब 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
दोपहर के सत्र में जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। इसके बावजूद विरोध जारी रहा। हंगामे के बीच उपसभापति ने सूचीबद्ध कार्यवाही जारी रखी और विधेयक पर चर्चा शुरू कराई। बाद में जब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले विधेयक पर बोल रहे थे, तब विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए। संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को भी उसी तरह कानूनी सुरक्षा देना है, जैसी सुरक्षा राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान को पहले से प्राप्त है।

इसके तहत 'वंदे मातरम' का अपमान, उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ माने जाने वाले कृत्य कानून के दायरे में आएंगे। विधेयक में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। 'वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और बाद में इसे उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया। आजादी के आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख प्रतीक बना और बाद में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। नए संशोधन के बाद यह बहस भी तेज हो सकती है कि कानून में 'अपमान' और 'बाधा' की परिभाषा क्या होगी तथा क्या इसमें जानबूझकर व्यवधान पैदा करने और किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय गीत के गायन में शामिल न होने के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा।

दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी: 1 अगस्त से शुरू होगी 'लक्ष्मी योजना', हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये

नई दिल्ली। बीजेपी सांसदों कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने बुधवार को दिल्ली की महिलाओं से लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्टर करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मिल सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली की सांसद स्वराज ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'मातृवत स्नेह' का उदाहरण है। स्वराज ने कहा कि इस योजना से लगभग 17 लाख महिलाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है और यह 1 अगस्त से शुरू होगी। मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को मंज़ूरी दी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। यह योजना पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी का चुनावी वादा थी। पश्चिमी दिल्ली की सांसद सहरावत ने कहा कि बीजेपी अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के अलावा, मुख्यमंत्री गुप्ता ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लखपति बिटिया योजना, स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण और मेरी पूंजी मेरा अधिकार जैसी अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं।

राहुल गांधी का बड़ा दावा- शिक्षा मंत्रालय को धर्मेंद्र प्रधान नहीं आरएसएस चला रहा है

नई दिल्ली।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर शिक्षा व्यवस्था पर 'कब्जा' करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस को छात्रों का 'असली दुश्मन' बताया और कहा कि वे छात्रों को 'अंधभक्त' बनाना चाहते हैं। सदन में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था का तेज़ी से निजीकरण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि शैक्षणिक संस्थानों और नीति-निर्माण पर आरएसएस का काफ़ी प्रभाव है।

हर चीज का हो रहा है निजीकरण

उन्होंने कहा, 'हमारी (शिक्षा) व्यवस्था बहुत खराब और क्रूर है; हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है... यह उगाही करने वाली व्यवस्था है, यह एक बेरहम और भयानक व्यवस्था है...
इस व्यवस्था पर कब्ज़ा कर लिया गया है; आरएसएस ने इस व्यवस्था की आत्मा पर कब्ज़ा कर लिया है... रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सिर्फ़ दिखावा है क्योंकि मंत्रालय प्रधान नहीं चलाते थे; शिक्षा मंत्रालय को चलाने वाला व्यक्ति और संगठन आरएसएस है और इसे चलाने वाला व्यक्ति मंत्री के ऑफ़िस में बैठा हुआ है।'

छात्रों पर इतिहास थोपने की कोशिश की जा रही है

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि आरएसएस छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी रुचि के अनुसार काम करने देने के बजाय, उन पर इतिहास का एक ऐसा रूप थोपने की कोशिश कर रही है जिसे उन्होंने 'विकृत' बताया। उन्होंने कहा, 'छात्रों को इस बात से परेशानी है कि उन्हें भारत में छात्र बने रहने की आज़ादी नहीं है।

उन्हें अपने जुनून को पूरा करने, अपनी बात कहने या सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है; बल्कि उन्हें आरएसएस की कल्पनाओं पर आधारित बेतुका इतिहास मानना पड़ता है। उन्हें इस ढांचे को स्वीकार करना पड़ता है। 'गांधी ने यह भी दावा किया कि देश भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का नेतृत्व ऋरूस से प्रभावित है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन शिक्षा व्यवस्था को आकार देने वाली मुख्य शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा, 'आज भारत के हर विश्वविद्यालय में - और छात्रों को यह पता होना चाहिए - वाइस चांसलर आरएसएस से हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो बस एक प्रतीक हैं; आपका असली दुश्मन आरएसएस है; वे आपको छात्र नहीं रहने देना चाहते, वे चाहते हैं कि आप 'अंधभक्त' बनें।' अपनी आलोचना जारी रखते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा कि चल रहा छात्र आंदोलन उस चीज़ को बड़े पैमाने पर नकारने का प्रतीक है, जिसे उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को तय करने की कोशिशें बताया। 'यह भारत की आत्मा की प्रतिक्रिया है जो कह रही है कि 'किसी भी हाल में हम आपके 'अंधभक्त' नहीं बनेंगे, किसी भी हाल में आप हमारा भविष्य तय नहीं करेंगे, और किसी भी हाल में हम आपकी बात नहीं मानेंगे।' इन बच्चों के माता-पिता में बीजेपी या आरएसएस का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी, ये बच्चे - जो बहादुर, कल्पनाशील और सशक्त हैं - डटे रहे और उन्होंने हर उस चीज़ का सामना किया जो उन पर फेंकी गई,' गांधी ने आगे कहा।

ई-20 पर केंद्र सरकार घिरी?: केजरीवाल का दावा- ऑटो कंपनियां डर के साए में, 30 करोड़ वाहन हो जाएंगे कबाड़

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ई-20 पेट्रोल को लागू करने के लिए 'गुंडागर्दी' पर उतर आई है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से वर्ष 2023 से पहले बने करीब 30 करोड़ वाहन कबाड़ बन जाएंगे और केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों को चुप रहने के लिए धमका रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले मैंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वर्ष 2023 से पहले बने वाहनों में ई-20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यह भी पूछा कि अगर इससे वाहन खराब होते हैं या माइलेज कम होता है तो क्या कंपनियां मुआवजा देंगी। किसी कंपनी ने आधिकारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने नौ कंपनियों के अधिकारियों से बात की।'

'कंपनियों को मोदी सरकार से मिल रही धमकी'

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कंपनियां डर के माहौल में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे बताया कि मोदी सरकार उन्हें धमका रही है। उन्होंने माना कि वर्ष 2023 से पहले बने वाहनों में ई-20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंजन को नुकसान होगा और माइलेज भी घटेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम यह बात सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे

प्लांट बंद करा दिए जाएंगे या ईडी की रेड पड़ जाएगी। मोदी जी 2023 से पहले बने 30 करोड़ वाहनों को कबाड़ बनाने पर तुले हुए हैं।'

ई-20 के लिए करेंगे आंदोलन

उन्होंने एथेनॉल के फायदे पर भी सवाल उठाते हुए कहा, 'इससे विदेशी मुद्रा की कोई बचत नहीं होती और भूजल का भी दोहन होता है। आखिर मोदी जी इस पर इतने अड़े क्यों हैं? हमने ई-20 को लेकर एक टाउन हॉल आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन संविधान क्लब में पुलिस पहुंच गई और अनुमति रद्द करा दी। इनडोर कार्यक्रमों के लिए पहले कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। मोदी जी, आपको ई-20 का फैसला वापस लेना ही होगा, चाहे सम्मानपूर्वक वापस लें या फिर हम आंदोलन करके इसे वापस करवाएंगे।'

'एफआईआर पर बोला गया झूठ'

'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन की चेतावनी पर पूछे गए सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, 'उन्हें विरोध करना चाहिए, हम उनके समर्थन में हैं। देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने कहा था कि एफआईआर वापस ली जाएंगी। फिर यह झूठ क्यों बोला गया?' दिल्ली में जलभराव और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, 'उन्हें सरकार चलाते हुए दो साल हो गए हैं। हमारे कार्यकाल में हालात कभी इतने खराब नहीं रहे। वे बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में भी पूरी तरह विफल रहे हैं।'

लक्ष्मी योजना पर भी उठाए सवाल

'लक्ष्मी योजना' पर टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस योजना की पात्रता की शर्तें ऐसी रखी गई हैं कि अधिकांश महिलाएं इससे बाहर हो जाएंगी। उन्होंने कहा, 'इस योजना में इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि शायद ही कोई पात्र हो सके। दिल्ली की 1.25 करोड़ महिलाओं में से केवल 17 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। यह सिर्फ एक खोखला वादा है।'

सम्पादकीय...

धुंधलाती गुरु

भारतीय संस्कृति का प्राण यदि किसी एक तत्व में समाहित है, तो वह है-गुरु। गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली चेतना है। वह मनुष्य के भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाता है, उसके व्यक्तित्व को संस्कारित करता है और उसे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। प्रसिद्ध वचन-'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः'-केवल स्तुति नहीं, बल्कि गुरु की उस महत्ता का उद्घोष है जिसके बिना जीवन का कोई भी आयाम पूर्ण नहीं हो सकता। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, कृतज्ञता और जीवन-मूल्यों के पुनर्जागरण का अवसर है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन है। जिसने जीवन को सही दिशा दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। भारतीय परंपरा में इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और भारतीय ज्ञान-परंपरा को सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। उन्होंने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि मानवता को विचारों की ऐसी ज्योति दी जो सहस्राब्दियों से विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा ज्ञान और जीवन-दृष्टि के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं है। शिक्षक सूचना देता है, गुरु चेतना जगाता है। शिक्षक बुद्धि को विकसित करता है, गुरु व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। शिक्षक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन गुरु सदैव तपस्वी होता है। गुरु वह है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को हटाकर आत्मविश्वास, विवेक और करुणा का दीप प्रज्वलित करे। गुरु का स्पर्श केवल मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता, वह आत्मा तक उतरता है। मेरे जीवन में गुरु का स्वरूप केवल एक पूज्य व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्रकाश-स्तंभ का रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने अपने प्रत्यक्ष सान्निध्य, प्रेरणाओं और जीवन-दृष्टि से मुझे बार-बार यह अनुभव कराया कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे जीवन के प्रत्येक अंधकार में दिशा दिखाने वाले दिव्य पथ-प्रदर्शक होते हैं। अनेक ऐसे अवसर आए, जब परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं, समाधान का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, लेकिन गुरु का स्मरण, उनकी वाणी और उनके द्वारा प्रदत्त संस्कारों ने सहज ही नई राह खोल दी। कई बार उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन ने ऐसी समस्याओं का समाधान किया, जो मानवीय दृष्टि से असंभव प्रतीत होती थीं। मैंने अनुभव किया है कि गुरु केवल वर्तमान का संबल नहीं बनते, वे भविष्य का निर्माण भी करते हैं। वे केवल सांसारिक जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा को भी आलोकित करते हैं। मृत्यु के पार के कल्याण का मार्ग भी गुरु ही प्रशस्त करते हैं। ऐसे अनुभव शब्दों में पूर्णतः व्यक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे तर्क से अधिक श्रद्धा, समर्पण और आत्मानुभूति के विषय हैं। आचार्य श्री तुलसी के प्रति मेरी अटूट निष्ठा का आधार कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके जीवन की तपश्चर्या, दूरदर्शिता, करुणा, आत्मीयता और वह दिव्य गुरु-शक्ति है, जिसने मेरे जीवन को बार-बार नई दिशा, नई चेतना और नई ऊँचाइयां प्रदान की हैं। आज दुनिया अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धियों के दौर से गुजर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति और तकनीकी विकास ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन क्या मनुष्य पहले से अधिक शांत, संतुलित और संवेदनशील हुआ है? उत्तर सहज नहीं है। ज्ञान बढ़ा है, परंतु विवेक घटा है। सूचना का विस्फोट हुआ है, लेकिन आत्मबोध का अभाव गहराया है। तकनीक ने गति दी है, पर दिशा देने वाला गुरु दुर्लभ होता जा रहा है। यही आधुनिक समय का सबसे बड़ा संकट है। आज शिक्षा संस्थान डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखा पा रहे। प्रतियोगिता बढ़ रही है, पर सहयोग घट रहा है। सफलता की दौड़ तेज हुई है, पर संतोष पीछे छूट गया है। ऐसे समय में गुरु पूर्णिमा केवल परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि जीवन की दिशा सुधारने का राष्ट्रीय और वैश्विक अभियान बनना चाहिए। गुरु का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वह केवल सफलता नहीं सिखाता, सार्थकता सिखाता है। वह केवल लक्ष्य तक पहुँचने की विधि नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। गुरु मनुष्य को बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना सिखाता है। आत्मसंयम, विनम्रता, सेवा, करुणा और सत्यनिष्ठा जैसे गुण गुरु के सान्निध्य में ही विकसित होते हैं। भारतीय इतिहास गुरु-शिष्य परंपरा के अनुपम उदाहरणों से भरा पड़ा है। श्रीराम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से मर्यादा सीखी। श्रीकृष्ण ने संदीपनि से शिक्षा ग्रहण की और स्वयं अर्जुन के जीवन में गुरु बनकर उसे कर्मयोग का संदेश दिया। भगवान महावीर के गणधर गौतम, भगवान बुद्ध के आनंद और गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद इस बात के प्रमाण हैं कि सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह नया व्यक्तित्व गढ़ता है। लेकिन आज गुरु की गरिमा अनेक कारणों से धूमिल हुई है। कुछ कथित गुरुओं ने अध्यात्म को प्रदर्शन, चमत्कार और व्यापार का माध्यम बना दिया है। श्रद्धा का स्थान प्रचार ने ले लिया है। आध्यात्मिकता की जगह बाजारवाद ने प्रवेश कर लिया है। ऐसे वातावरण में विवेकपूर्वक गुरु का चयन अत्यंत आवश्यक है। संतों ने ठीक ही कहा है-'पानी पीजै छान के, गुरु कीजै जान के।' गुरु वह नहीं जो भीड़ जुटाए, बल्कि वह है जो व्यक्ति के भीतर चरित्र, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करे। सच्चा गुरु कभी अपने व्यक्तित्व का प्रचार नहीं करता। उसका जीवन ही उसका संदेश होता है। वह अपने अनुयायियों को स्वयं पर आश्रित नहीं बनाता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। वह अंधभक्ति नहीं, आत्मजागरण सिखाता है। उसका मौन भी शिक्षा होता है और उसका आचरण सबसे बड़ा उपदेश। आज आवश्यकता केवल अच्छे गुरुओं की नहीं, बल्कि अच्छे शिष्यों की भी है। गुरु तभी प्रभावी होता है जब शिष्य में विनम्रता, जिज्ञासा और ग्रहणशीलता हो। अहंकार से भरा हुआ पात्र ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। इसलिए गुरु पूर्णिमा हमें केवल गुरु का सम्मान करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर योग्य शिष्य बनने की प्रेरणा भी देती है। यदि हम विश्व को अधिक शांतिपूर्ण, मानवीय और संतुलित बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होगा। नई विश्व-व्यवस्था का निर्माण आध्यात्मिक मूल्यों पर ही संभव है।
विज्ञान हमें साधन दे सकता है, लेकिन उनका सदुपयोग कैसे हो, यह गुरु ही सिखा सकता है।

लाठी और लोकतंत्र जैनरेशन जैड ने दिखाई राह

'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।' दिल्ली की सड़कों पर 37 दिनों तक चले निर्भीक, मुखर और डिजिटल दौर के युवा आंदोलन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समान, गुणवत्तापूर्ण और सार्थक शिक्षा केवल एक नीति का विषय नहीं, बल्कि युवाओं का संवैधानिक अधिकार है। कॉक्रोच जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने राजधानी को झकझोर दिया। नीट प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़े जवाबदेही के अभाव ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया तथा अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा सुधार की मांग गूंजने लगी। लेकिन इन मांगों का जवाब संवाद नहीं, बल्कि लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, निर्मम पिटाई और भरोसे के टूटने के रूप में मिला। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रदर्शनकारियों को अपेक्षित राहत नहीं मिली। अदालत की टिप्पणियां थीं, ''हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है।'' एक अन्य टिप्पणी थी, ''हमें इसमें मत घसीटिए।'' ऐसी प्रतिक्रियाओं ने भी युवाओं को निराश किया। प्रदर्शन स्थल की चश्मदीद गवाह होने से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वहां मौजूद युवा पुलिस की धमकियों से भयभीत नहीं थे। वे सरकार से कोई दान या कृपा मांगने नहीं आए थे। वे उस अधिकार की मांग कर रहे थे, जिसे वे संविधान द्वारा प्रदत्त अपना वैध अधिकार मानते हैं। ऐसा अधिकार, जिसे सत्ता की सुविधा के अनुसार दिया या छीना नहीं जा सकता। सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या समझा और उसका समाधान बल प्रयोग में खोजा। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। उसने प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताया और इसे आगामी चुनावों का मुद्दा बनाने में कोई देर नहीं लगाई। आखिर राजनीति में घायल सरकार की गंध से अधिक तेजी से नेताओं को और क्या आकर्षित कर सकता है? राजनीति में हर संकट किसी न किसी के लिए अवसर बन जाता है। चौंकाने वाली बात यह रही कि लाठियों ने केवल प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पूरे राजनीतिक वर्ग की मानसिकता को भी उजागर कर दिया, जो युवाओं का स्वागत तब तक करता है, जब तक वे तालियां बजाते रहें लेकिन जैसे ही वे सवाल पूछते हैं, उन्हें असुविधा महसूस होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का उत्तर संवाद से नहीं, बल्कि बल प्रयोग से दिया।

इससे केवल सरकार की असहमति के प्रति असहजता ही उजागर नहीं हुई, बल्कि यह भी सामने आया कि पूरा राजनीतिक वर्ग जनाक्रोश को लोकतांत्रिक चेतावनी की बजाय चुनावी पूंजी के रूप में देखने लगा है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा पाखंड पुलिस कार्रवाई नहीं था, बल्कि उसके बाद नेताओं द्वारा नैतिकता का चोला ओढ़ लेना था। चुनावों से पहले रोजगार, पारदर्शिता और अवसरों का वादा करने वाले वही नेता सत्ता में आने के बाद जनता की मांगों को चुनौती और अवज्ञा मानने लगते हैं। दरअसल सड़कों से जो सबसे बड़ा संदेश उभरकर सामने आया, वह यह कि आज का युवा उस राजनीति को अस्वीकार कर रहा है, जो अधिकारों को उपकार बनाकर प्रस्तुत करती है। वह उस राजनीतिक संस्कृति को भी चुनौती दे रहा है, जिसमें संवैधानिक अधिकारों को सत्ता की कृपा और जवाबदेही को वैकल्पिक गुण समझ लिया गया है। इतिहास बताता है कि लाठी किसी भी भीड़ को तितर-बितर कर सकती है लेकिन उस विचार को कभी समाप्त नहीं कर सकती, जिसका समय आ चुका हो। राजनीतिक दोहरेपन की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। जो कल पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, सत्ता से बाहर होते ही लोकतांत्रिक अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार बन जाते हैं। और जो कल सरकारी दमन की आलोचना कर रहे थे, सत्ता में आते ही वही कदम उचित ठहराने लगते हैं। फिर भी इस आंदोलन ने सत्ता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक छोड़े हैं। अब समय आ गया है कि शिक्षा को शासन और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया जाए। सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष अभी शेष हैं। ऐसे में आत्मप्रशंसा में डूबे रहने की बजाय उसे युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। इतिहास तय करेगा कि सरकार और न्यायपालिका इस चेतावनी को समय रहते समझ पाए या फिर जैनरेशन जैड स्वयं परिवर्तन का अगला अध्याय लिखेगी। परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने वालों के विरुद्ध कठोर कानून बनाना निश्चित रूप से आवश्यक है लेकिन वास्तविक सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली की पूरी संरचना और संचालन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करना होगा। इसके साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था का भी व्यापक पुनर्गठन आवश्यक है, क्योंकि देश तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के युग में प्रवेश कर रहा है। शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़कर देखना होगा। यदि सरकारें इस संदेश को समय रहते समझ लें, तो यह आंदोलन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक सकारात्मक मोड़ सिद्ध हो सकता है।

परिवार के बिना जान के जोखिम में बुजुर्ग

प्रतिदिन बहुत-से अखबार पढ़ती हूं। सोशल मीडिया पर भी पढ़ने को काफी सामग्री होती है। पिछले दिनों एक घटना पढ़कर दिल गई। एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर, बिहार में रहते थे। वह एक बैंक से कैशियर के पद से रिटायर हुए थे। उनका बेटा निखिल बेंगलुरु में नौकरी करता है। बेटे ने घर के सी.सी.टी.वी. को मोबाइल से जोड़ रखा था और समय-समय पर माता-पिता के हाल-चाल देखता रहता था। एक शाम 4 बजे, उसने मोबाइल पर देखा कि उसके पिता गिरे पड़े हैं और मां सीढ़ी की तरफ भाग रही है। उसने उनके मोबाइल पर फोन किया लेकिन वे स्विच्ड ऑफ थे। लड़का घबरा गया। उसने अपने पड़ोसी अमित को फोन करके कहा कि उसके घर जाकर देखें। माता-पिता पर किसी ने हमला कर दिया है। 3-4 लोग घर में दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी अमित कुछ अन्य पड़ोसियों के साथ घर पहुंचा तो देखा कि निखिल के पिता पहली मंजिल पर पड़े थे। उन पर अनेक बार चाकू से हमला किया गया था। मृत्यु हो चुकी थी। पिता की कुछ दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुई थी। उन्हें स्वास्थ्य की अन्य परेशानियां भी थीं। बुजुर्ग भी थे। ऐसे में हत्यारों का मुकाबला करते भी तो कैसे। बुजुर्ग 4 भाई थे। 2 की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। भाइयों के चले जाने से भी वह परेशान रहते थे लेकिन पूछने पर कभी कुछ नहीं बताते थे। फिर पड़ोस के लोग निखिल की मां को ढूंढने लगे। ऊपर वह भी मरी हुई मिली। उनके हाथ बंधे हुए थे। और उनके मुंह पर टेप लगा था। गमछे से गला घोंटा गया था। पड़ोसियों ने वापस बेंगलुरु में निखिल को फोन किया। पुलिस को भी बुलाया। घर में रहने वाली एक और किराएदार ने ही पुलिस को सूचना दी कि बुजुर्गों ने दूसरी मंजिल पर 4 दिन पहले एक लड़के को किराएदार रखा था। सामान के नाम पर वह लड़का अपने साथ एक बैग और एक सिलेंडर ही लाया था। एक बार आने के बाद वह दोबारा आया। पीने का पानी मांगा, फिर किसी को दिखाई नहीं दिया। महिला किराएदार ने यह भी कहा कि शाम साढ़े 5 बजे आंटी पानी भरने के लिए मोटर चलाती थीं। आज नहीं आईं तो आवाज भी लगाई लेकिन वह नहीं आईं। सी.सी.टी.वी. में वह किराएदार भागते भी दिखाई दे रहा था। किराएदार को ढूंढने पर वह कहीं नहीं मिला। उसका सामान भी गायब था। दम्पति के मोबाइल फोन भी गायब थे। बेटे निखिल ने बताया कि किराएदार ने अपना आधार कार्ड भी उसके पिता को दिया था लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बुजुर्गों की बेटी ने कहा कि उसके माता-पिता की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। इन दिनों पुलिस कहती है कि कोई भी किराएदार रखने से पहले पुलिस वैरीफिकेशन करा ली जाए। क्या किराएदार का पुलिस वैरीफिकेशन नहीं कराया था? यदि कराया होता तो शायद ये बुजुर्ग दम्पति बच जाते। हालांकि यह भी सच है कि लोग पुलिस के पास जाने से बचते हैं। इसके अलावा यदि पुलिस से वैरीफिकेशन करा भी लें, तो पुलिस हर वक्त तो कहीं मौजूद नहीं रह सकती। वह भी किसी घटना-दुर्घटना के हो जाने के बाद ही पहुंचती है। हां, किराएदार की जानकारी जरूर पलक झपकते ही मिल सकती थी। भागने पर भी उसकी जल्द पहचान हो जाती। पूरी घटना से यह बात भी सामने आती है कि जरूर उस लड़के ने अपराध की मंशा से ही बुजुर्गों का मकान किराए पर लिया होगा।

अमेठी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान बना स्वावलंबन का पर्याय

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (एमवाईयूवीए) राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेष तथा स्वावलंबन की नई क्रांति का सूत्रपात कर रही है।

प्राकृतिक संसाधनों और वनांचल से समृद्ध जनपद सोनभद्र में यह अभियान युवाओं के सपनों को साकार कर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक नई और सकारात्मक दिशा दे रहा है। प्रदेश सरकार का मूल ध्येय राज्य के प्रत्येक युवा को इतना सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है कि वे न केवल अपने रोजगार का सृजन करने में सक्षम हो सकें अपितु रोजगार प्रदाता का स्वाभिमान भी अर्जित कर सकें। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से शिक्षित, प्रशिक्षित और प्रतिभावान युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने हेतु व्यापक वित्तीय तथा संस्थागत संबल प्रदान किया जा रहा है, जिससे जनपद के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का जज्बा जागृत हुआ है। जनपद सोनभद्र में जिला प्रशासन के कुशल निर्देशन एवं सतत अनुश्रवण में इस जनकल्याणकारी योजना का अत्यंत प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर आयोजित जागरूकता शिविरों, परामर्श कार्यक्रमों एवं बैंक समन्वय बैठकों के माध्यम से योजना के प्रावधानों, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की सटीक जानकारी दूर-दराज के ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के पात्र युवाओं तक पहुँचाई जा रही है। जनपद सोनभद्र निवासी युवा उद्यमी रवि अग्रहरि की सफलता की गाथा इस बात का जीवंत और सशक्त प्रमाण है कि सुदृढ़ इच्छाशक्ति तथा शासकीय प्रोत्साहन के संयोजन से युवा वर्ग अपने सपनों को साकार करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान दे सकता है। रवि अग्रहरि लंबे समय से स्वरोजगार के बेहतर अवसरों की खोज में प्रयासरत थे। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक जागरूकता शिविर में उन्हें इस युगांतकारी अभियान की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। शिविर में उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कुशलता और अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया और 'हेल्थ नेचुरल थैरेपी सेंटर' की एक ठोस कार्ययोजना तैयार की। प्रस्ताव के समुचित परीक्षण के उपरांत स्थानीय बैंक शाखा द्वारा रवि अग्रहरि को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण शीघ्रता से स्वीकृत किया गया। जिला प्रशासन द्वारा सुलभ कराई गई इस त्वरित वित्तीय सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन की बदौलत रवि अग्रहरि ने आवश्यक मशीनरी, आधुनिक उपकरण एवं फर्नीचर क्रय कर अपने सेंटर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया। उच्च गुणवत्तायुक्त सेवाओं और सामाजिक प्रतिबद्धता के बल पर उनका यह थैरेपी सेंटर अत्यंत कम समय में जनपद सोनभद्र में एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। वर्तमान में उनके व्यवसाय का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर में भी व्यापक और गुणात्मक सुधार आया है। इस सफलता का सबसे अनुकरणीय पहलू यह है कि रवि अग्रहरि ने स्वयं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ क्षेत्र के तीन अन्य स्थानीय नागरिकों को भी अपने संस्थान में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। इस प्रकार वे जनपद में प्रदेश सरकार के उस मूल उद्देश्य को साकार कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ नौकरी देने वाला (जॉब क्रिएटर) बनाना है। 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को तेजी से बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सीधे लाभान्वित करना है, जिसके अंतर्गत अगले दस वर्षों में दस लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने की एक विस्तृत और दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की गई है। इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि युवाओं को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए बैंकों के माध्यम से बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सोनभद्र के उन मेधावी युवाओं को ऐतिहासिक राहत मिली है, जो पूंजी और वित्तीय संसाधनों के अभाव में अपने उत्कृष्ट व्यापारिक विचारों को धरातल पर नहीं उतार पाते थे। योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है, साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदकों को भी इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अथवा आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को इस अभियान में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अभियान के प्रथम चरण के सफल संचालन के बाद, व्यवसाय के कुशल संचालन और ऋण का समय पर भुगतान करने वाले उद्यमियों के लिए द्वितीय चरण का प्रावधान भी किया गया है। द्वितीय चरण में योग्य सूक्ष्म उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार हेतु 10 लाख रुपये तक का द्वितीयक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और अनुदान का लाभ निरंतर जारी रखा जाएगा। वित्तीय सहायता के साथ-साथ योजना के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक व्यावसायिक कौशल, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने व्यवसाय को सुगमता से संचालित कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और बैंक स्वीकृति में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त अनुदान का भी आकर्षक प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। सोनभद्र में स्थानीय स्तर पर नए उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र के प्रचुर संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन में भी भारी कमी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद में योजना का नियमित एवं गहन अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को समय पर वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। रवि अग्रहरि की यह उल्लेखनीय सफलता जनपद सोनभद्र के अन्य युवाओं के लिए एक सम्मानित जीवन की राह में आत्मनिर्भरता के लिए सफलता प्राप्त करने की प्रेरणादायक मिसाल के रूप में है। प्रदेश सरकार की सही नीति, दृढ़ संकल्प और सक्रिय शासकीय सहयोग से आज दूरस्थ अंचलों में भी आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं।

कनेक्टिविटी की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

किसी भी राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास का आधार उसकी सुदृढ़ आधारभूत संरचना होती है तथा सड़क संपर्क इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित सड़क नेटवर्क न केवल आवागमन को सुगम बनाता है, बल्कि व्यापार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, निवेश तथा रोजगार के अवसरों को भी नई गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क अवसंरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसी क्रम में सीमावर्ती एवं अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य की सीमाएं नेपाल सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार जैसे राज्यों से जुड़ी हुई हैं। इन सीमाओं के माध्यम से प्रतिदिन लाखों नागरिकों, व्यापारिक वाहनों एवं पर्यटकों का आवागमन होता है। ऐसे में सीमावर्ती एवं अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों का उच्च गुणवत्ता वाला विकास प्रदेश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुल 158 सीमावर्ती एवं अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों का चयन पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए किया गया है। इन मार्गों की कुल लंबाई 2877 कि0मी0 है, जो प्रदेश के दूरस्थ गांवों, सीमावर्ती क्षेत्रों एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इन मार्गों के विकसित होने से कृषि उत्पादों, औद्योगिक वस्तुओं एवं आवश्यक सेवाओं का परिवहन अधिक तीव्र, सुरक्षित एवं किफायती होगा। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ₹4330.35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस निवेश के अंतर्गत केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार पुल एवं पुलियों का निर्माण, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधान, सुदृढ़ तथा दीर्घकालिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। यह निवेश प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना विकसित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। प्रदेश सरकार की इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। चयनित 158 मार्गों में से 126 मार्ग पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि शेष परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य प्रगति पर है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं समयसीमा के अनुरूप पूर्ण कराने के लिए सतत निगरानी एवं नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश सरकार केवल उत्कृष्ट सड़क नेटवर्क के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नागरिक एवं पर्यटक को एक सकारात्मक एवं आकर्षक अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भव्य स्वागत द्वारों के निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 143 मार्गों पर स्वागत द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर लगभग ₹232.99 करोड़ की लागत व्यय की जा रही है।

अब तक 83 स्वागत द्वारों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष पर कार्य प्रगति पर है। इन स्वागत द्वारों की रूपरेखा में आधुनिक स्थापत्य कला के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का समावेश किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों, पर्यटकों एवं निवेशकों पर राज्य की सकारात्मक एवं विकसित छवि का प्रभाव पड़ता है। सीमावर्ती एवं अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों के विकास से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त हो रही है। विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा आयात-निर्यात की प्रक्रिया अधिक सुगम एवं समयबद्ध हुई है। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन लागत में कमी आने के साथ-साथ मालवाहक वाहनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बल मिला है। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा यह आधुनिक सड़क नेटवर्क पर्यटन क्षेत्र के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अयोध्या धाम, काशी, मथुरा-वृंदावन सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा आने वाले यात्रियों के लिए सुगम एवं सुरक्षित संपर्क मार्ग तथा आकर्षक स्वागत द्वार उनके यात्रा अनुभव को और अधिक सहज एवं यादगार बना रहे हैं, जिससे पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित हो रहा यह सुदृढ़ सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़क संपर्क से सुरक्षा एजेंसियों एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होती है, जिससे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई संभव हो पाती है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए समावेशी एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। सीमावर्ती एवं अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों की यह व्यापक पहल उत्तर प्रदेश को देश के सर्वाधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक कनेक्टिविटी वाले राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है तथा विकसित उत्तर प्रदेश एवं एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सायं पॉकेटमता एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

भटनी शरीफ के अमजद खान 'तमन्ना' राष्ट्रीय वक्फ सम्मेलन में होंगे सम्मानित वक्ता

भटनी देवरिया।

दरबारे मौला भटनी शरीफ के सज्जादा नशीन एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमजद खान 'तमन्ना' आगामी 1 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय वक्फ एवं मदरसा सम्मेलन में विशेष वक्ता के रूप में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन में देशभर से उलेमा, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अमजद खान 'तमन्ना' ने बताया कि सम्मेलन में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, पारदर्शी प्रबंधन तथा

मदरसा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने

एक अगस्त को दिल्ली में वक्फ संपत्तियों व मदरसा शिक्षा के मुद्दों पर रखेंगे विचार

बताया कि वर्तमान समय में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और मदरसों के विकास जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। ऐसे में यह सम्मेलन सार्थक संवाद का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि भटनी शरीफ का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में भाग लेना उनके लिए गौरव की बात है।

जनता दर्शन में गूंजा भूमि अतिक्रमण का मामला, डीएम के निर्देश पर तुरंत पहुंची राजस्व टीम

देवरिया।

जनसुनवाई और भूमि विवादों के त्वरित समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान ग्राम बहोरपुर निवासी सुमित्रा देवी पत्नी महेंद्र यादव ने गाटा संख्या 270 (क्षेत्रफल 0.134 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे की गंभीर शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने एसडीएम सदर को तत्काल राजस्व टीम भेजकर मौके पर पारदर्शी जांच कराने और आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ?जिलाधिकारी के सख्त रुख के बाद उपजिलाधिकारी सदर के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल की संयुक्त टीम ने बहोरपुर पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। मौके पर की गई पैमाइश और अभिलेखों की पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि संबंधित गाटा संख्या सरकारी खलिहान की श्रेणी में दर्ज है। इसके कुछ हिस्से पर स्थानीय कब्जाधारियों द्वारा मकान व सहन बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि कब्जाधारियों के पास रहने के लिए इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है और आवागमन का मार्ग भी इसी भूखंड से होकर गुजरता है। तहसील प्रशासन ने मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कब्जाधारियों को अतिक्रमित सरकारी भूमि खाली करने के लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम सदर ने बताया कि जनता दर्शन में मिली शिकायत पर उसी दिन टीम भेजकर कार्रवाई अमल में लाई गई। कब्जाधारियों को तय समय के भीतर अतिक्रमण हटाने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी भूमि को मुक्त नहीं कराया जाता है, तो नियमानुसार आगे की प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जर्जर बिजली तारों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सबस्टेशन पर प्रदर्शन कर भेजा ज्ञापन

बड़हलगंज।

क्षेत्र के नरहरपुर गांव में जर्जर विद्युत तारों और बदहाल बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, अधीक्षण अभियंता, खंड विकास अधिकारी, सांसद, विधायक समेत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर तत्काल सुधार कार्य कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लंबे समय से बिजली आपूर्ति की स्थिति बदहाल है।

आए दिन फ्यूज उड़ना, तार टूटना, लो-वोल्टेज की समस्या तथा बार-बार बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार घंटों तक आपूर्ति बाधित रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय

द्वितीय से श्रद्धानंद मिश्र के घर तक कई स्थानों पर बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे हैं। इससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है तथा किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विद्युत विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने मांग की कि आवश्यकता के अनुसार नए विद्युत पोल लगाए जाएं, जर्जर एवं नीचे लटक रहे तारों को तत्काल बदला जाए तथा पूरी विद्युत लाइन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ और कोई दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी

नए पोल लगाने, लटकते तार बदलने और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा मंत्री, अधीक्षण अभियंता (गोरखपुर), खंड विकास अधिकारी, सांसद, विधायक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी ज्ञापन भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन पर ग्राम प्रधान हरिओम मिश्र, संतोष मिश्र, अभय कुमार, शैलेश मिश्र, विमल मिश्र, रघुवीर, रामकेश्वर यादव, सतीश यादव, अरुण कुमार शुक्ल, व्यासनाथ यादव, विशाल मौर्य, शशिकांत मौर्य, अखिलेश मौर्य, कैलाश गुप्ता, मनीष पांडेय, नंदकुमार पांडेय, राहुल मिश्र समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।

गन्ना सर्वे-सट्टा प्रदर्शन की शिकायतों का होगा समयबद्ध निस्तारण, नए सदस्य भी बन सकेंगे

कुशीनगर।

पेराई सत्र 2026-27 के लिए जनपद में गन्ना ग्राम स्तरीय सर्वे-सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम 20 जुलाई से 30 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। इस दौरान गन्ना किसानों की शिकायतों का मौके पर पंजीकरण कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। साथ ही, गन्ना समिति के नए सदस्य बनाने का अभियान भी जारी है। जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने बताया कि जनपद के 1488 राजस्व गन्ना ग्रामों में सर्वे-सट्टा प्रदर्शन के लिए राजकीय गन्ना पर्यवेक्षकों एवं चीनी मिल कर्मियों की 181 संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान किसानों की आपत्तियां मौके पर ही आपत्ति रजिस्टर में दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से कुल 1185 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें गन्ना सर्वे से संबंधित 455, कृषि योग्य भूमि 177, गाटा 92, आधार संख्या 66, बैंक खाता 39, प्रजाति संशोधन 21, सप्लाई मोड 108, मोबाइल नंबर सुधार 176, ट्रांसफर एंट्री 46 तथा पारिवारिक सट्टा से संबंधित पांच शिकायतें शामिल हैं। इन सभी शिकायतों का परिषद एवं समिति स्तर पर समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे सर्वे-सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान अथवा संबंधित गन्ना विकास परिषद एवं गन्ना समिति में संपर्क कर अपनी शिकायतें समय से दर्ज कराएं, ताकि उनका शीघ्र एवं सही समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत जो गन्ना कृषक अब तक गन्ना समिति के सदस्य नहीं बन सके हैं, वे गन्ना समिति अथवा चीनी मिल स्तर पर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता के लिए कृषक से केवल 21 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि 200 रुपये अंश राशि भविष्य में गन्ना आपूर्ति की पहली पर्ची से समायोजित कर अंश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली परिक्षेत्र हाई अलर्ट, डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चार जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए व्यापक दिशा-निर्देश

बरेली।

आगामी श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी ने परिक्षेत्रीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, घाटों की सुरक्षा, साफ-सफाई तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पुलिस के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निकाय, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। डीआईजी ने निर्देशित किया कि सभी कांवड़ शिविर प्रशासन की अनुमति के बाद ही लगाए जाएंगे। शिविर एवं कांवड़ स्टैंड सड़क से पर्याप्त दूरी पर बनाए जाएंगे ताकि यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाओं की संभावना कम रहे। हाईवे पर यथासंभव सभी शिविर सड़क की बाईं ओर स्थापित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को सड़क पार न करनी पड़े। प्रत्येक शिविर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या कांवड़ खंडित करने जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। शिविरों में ड्यूटी करने वाले सभी सेवादारों एवं कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा।महिला कांवड़ियों के लिए शिविरों में अलग वाशरूम, विश्राम कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ मिशन शक्ति सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं, आग से सुरक्षा के लिए प्रत्येक शिविर में टीन शेड, फायर एक्सटिंग्विशर तथा अन्य अग्निशमन उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। कांवड़ मार्ग को सुपर जोन, जोन, सेक्टर एवं सब-सेक्टर में विभाजित कर पुलिस की पैदल एवं बाइक गश्त बढ़ाई जाएगी। रिजर्व पुलिस बल को मार्ग के निकट तैनात रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात

कांवड़ मार्गों पर रहेगा हाईटेक सुरक्षा घेरा, ICCC से होगी लाइव निगरानी, कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट, चौड़ाई 10 फीट और डीजे की आवाज 75 डेसिबल तक सीमित

स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। धार्मिक स्थलों, प्रमुख चौराहों तथा उन स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे कांवड़ झांकियां देखने पहुंचते हैं, वहां अतिरिक्त पुलिस बल एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बरेली रिजर्व पुलिस लाइन में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां से बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के प्रमुख कांवड़ मार्गों, घाटों, मंदिरों और चौराहों की लाइव निगरानी की जाएगी। कांवड़ मार्गों पर लगाए गए सीसीटीवी एवं आईपी कैमरों की निगरानी परिक्षेत्र कार्यालय की कांवड़ सेल भी करेगी। बदायूं के कछला घाट पर अस्थायी थाना, चार पुलिस चौकियां, चार वॉच टावर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम तथा वायरलेस संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सभी जनपदों को अपने-अपने घाटों, प्रमुख मंदिरों एवं कांवड़ मार्गों का विस्तृत मानचित्र एवं आंकड़े तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दुर्घटना और गौकशी पर रहेगी विशेष निगरानी

डीआईजी ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं, गौकशी तथा अन्य संवेदनशील घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए। पिछले तीन वर्षों में डायल-112 पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण कर पूर्व से ही प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। प्रत्येक कांवड़ जत्थे के लिए चौकीवार नोडल उपनिरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जत्थों का पूरा विवरण, संपर्क सूत्र एवं परिचय पत्र पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा। कांवड़ियों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र पर संबंधित हल्का प्रभारी एवं थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर अंकित होगा। कांवड़ मार्ग से जुड़े गांवों के ग्राम प्रधानों के साथ भी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के बीच संयुक्त रूट डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। दूध, दवा, अखबार, राशन एवं पशु चारा जैसे आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए अलग मार्ग एवं समय निर्धारित किया जाएगा। मार्गों पर रिफ्लेक्टरयुक्त सीमेंटेड बैरियर लगाए जाएंगे तथा पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार सार्वजनिक घोषणाएं की जाएंगी। जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहां वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाएंगे।

अस्पतालों में बेड रिजर्व, बाइक एम्बुलेंस रहेंगी तैनात

कांवड़ मार्ग से जुड़े सभी अस्पतालों में श्रद्धालुओं के लिए बेड आरक्षित रखे जाएंगे। मोटर बाइक एम्बुलेंस, जनरेटरयुक्त मोबाइल प्रकाश व्यवस्था तथा आपातकालीन राहत वाहन तैनात रहेंगे। घाटों पर एसडीआरएफ , फ्लड पीएसी, गोताखोर, नाव, लाइफ जैकेट, बैरिकेडिंग एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कांवड़ और डीजे के लिए तय किए गए मानक

रेलवे लाइन एवं बिजली के तारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तथा अधिकतम चौड़ाई 10 फीट निर्धारित की गई है। वहीं डीजे की ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक नहीं होगी। डीजे वाहनों की लंबाई, चौड़ाई एवं ध्वनि स्तर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शराब और मांस की दुकानों पर रहेगी विशेष निगरानी

कांवड़ मार्ग पर स्थित शराब एवं मांस की दुकानों तथा मांस परोसने वाले ढाबों और होटलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से पूरे मार्ग की साफ-सफाई, कूड़ेदानों को ढकवाने तथा मृत पशुओं को तत्काल हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बरेली के सात प्रमुख नाथ मंदिरों सहित सभी प्रमुख शिवालयों एवं अन्य जिलों के प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान बैरिकेडिंग, कतार व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूर्व निरीक्षण किया जाएगा। संबंधित मंदिर प्रबंधन समितियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि आगामी श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और समन्वय के साथ संपन्न कराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई कि वे प्रशासन का सहयोग करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में अपनी सहभागिता निभाएं।

स्टूडेंट, इडियट्स और अंधभक्तः राहुल ने छात्रों की बताई तीन कैटेगरी तो भाजपा हुई हमलावर, कहा- ये अक्षम्य

नई दिल्ली । लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों को लेकर जो टिप्पणी की, वह अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों को 'स्टूडेंट, इडियट्स और अंधभक्त' जैसी श्रेणियों में बांटने की कोशिश की, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों पर गोली चलने का जो आरोप लगाया, वह पूरी तरह झूठा है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि संसद परिसर के भीतर राहुल गांधी खुद को भी 'इडियट' नहीं कह सकते और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद अपनी सच्चाई जानते हैं और देश भी उसे जानता है। पात्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के मेधावी छात्र अपनी मांगों को लेकर सामने आए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने छात्रों से बातचीत की, समाधान निकाला और इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक पेपर लीक रोकने, परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करने का मुद्दा लंबित रहा, लेकिन अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

भाजपा ने राहुल के कौन से झूठ को किया बेनकाब?

अमित शाह तीस गाड़ी से चलते हैं।
प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई गई।
अमित शाह सदन में आने से कांप रहे।
अमित शाह डर के मारे छुपे हुए हैं।
आरएएफ ने छात्राओं के कपड़े फाड़े।
राहुल का माइक ऑफ कर दिया जाता है।

क्या छात्रों पर गोली चलने का दावा झूठा बताया गया?

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। भाजपा ने तथ्यों की जांच के बाद स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कोई गोली नहीं चली और राहुल गांधी ने झूठा दावा किया है। पात्रा ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है और इससे भ्रम फैलता है।

गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी पर क्या कहा?

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के उस सवाल पर भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में क्यों मौजूद नहीं थे। पात्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री केवल भाजपा के नहीं, बल्कि पूरे देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग गृह मंत्री का सम्मान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री उनकी तरह गुप्त विदेश यात्राओं पर नहीं जाते, बल्कि देश की जिम्मेदारियां निभाते हैं।

पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर भाजपा का क्या दावा?

संबित पात्रा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। उनके अनुसार, सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

एमपी में किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार

अब 60% मूंग की होगी खरीदी; ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया था। इस समूह की किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में कई किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । इसके संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। हमारे अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार है और उनके परिश्रम से उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते है भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों से उनकी उपज का 25 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जाएगा। मंत्री कंसाना ने बताया कि आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 25 प्रतिशत नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले । मंत्री कंसाना ने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यावहारिक समस्याओं का प्रश्न है, यह व्यवस्था राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण सुधार है और आने वाले समय में इससे किसानों को काफी सुविधा एवं लाभ मिलेगा।

किसानों के लिए नई व्यवस्था

मंत्री कंसाना ने कहा कि क्योंकि यह एक नई व्यवस्था है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त, की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे । सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई-टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है।

राहुल बोले- छात्रों पर दिल्ली में पैलेट गन चलीः नुकीली लाठियां मारी गई

नई दिल्ली । राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता की । इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अमित शाह पर कुछ बोला, मैंने कहा कि जो भी छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। इसीलिए मुझे नहीं बोलने दिया गया। मुझसे ये आश्वासन दिया गया कि मैं अगर माफी मांग लूं तो मैं अपना संबोधन जारी रख सकता हूं। मैं कभी भी भाजपा और आरएसएस वालों से माफी नहीं मांगूंगा। ये उनको समझना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि देश की समस्याओं पर बोलूं। और इस समय सबसे बड़ी समस्या छात्रों पर हुई बर्बरता है। मैं इस पर बोलूंगा। वहां, छात्रों को डंडों से मारा गया वो भी उन डंडों में कीलें लगाई गई थीं। उनको कहां ये आइडिया आया। कई वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वालों ने लड़कियों को और बच्चों को मारा। आगे उन्होंने कहा कि अब सवाल ये उठता है कि जो भी कार्रवाई पुलिस करती है, जो गृह मंत्रालय से जुड़े होते हैं या वहां रिपोर्ट करते हैं। उन्हें गृह मंत्री के आदेश की जरूरत पड़ती है। मैंने खुद देखा है कि अमित शाह पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहे थे, अफसर खुद फोन पर बोले अमित शाह जी। मैंने देखा कि मंत्री जितेंद्र सिंह को अमित शाह का लगातार फोन आ रहा था। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि उस दिन वहां छात्रों के साथ क्या हो रहा था। अब यहां दो संभावनाएं है कि उन्होंने खुद आदेश दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल करें। उनपर लाठियां चलाएं, जिनमें कीलें लगी थीं। और दूसरी कि वो खुद नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा था। इसके अलावा कोई और तीसरी संभावना नहीं हो सकती। जो भी छात्र वहां मारे गए है, उन्हें पता होना चाहिए, कि आपको जो भी हुआ उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। अब एक और बात कौन किसे रिपोर्ट करता है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। गृह मंत्रालय अमित शाह संभालते है। जो गृह मंत्री है। बच्चों पर कार्रवाई करने वाली दिल्ली पुलिस थी और दूसरी आरएएफ थी। ये आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करती है, जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाई। वो दोनों फोर्स गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले ही क्रूर है-राहुल गांधी

इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि कई लोगों को लगता है कि छात्रों को पेपर लीक की वजह से गुस्सा आया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले ही क्रूर है। लाखों रुपये गरीबों से लिए जाते है। हर चीज प्रायवेटाइज्ड है। पेपर लीक, एक परीक्षा में कुछ होता है, दूसरे में कुछ। एक में रिएग्जाम होता है, दूसरे में नहीं होता है। यह एक बेहद खराब व्यवस्था है। यह सिस्टम और इसकी आत्मा को कब्जे में कर लिया गया है। इसे आरएसएस ने कब्जे में किया है। राहुल ने आगे कहा- राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम यूपीए नहीं है, हमारे मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते। वो सही कह रहे है।

यहां जो हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कभी नहीं चलाते। उसे आरएसएस चलाता है। मंत्री के दफ्तर में बैठा एक ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी)। छात्रों को कुछ बोलने नहीं दिया जाता। उन्हें अपने मन की चीज फॉलो नहीं करने दी जाती। उन्हें वह इतिहास पढ़ना पढ़ता है, जो आरएसएस लाना चाहता है। हर यूनिवर्सिटी में आज आरएसएस से जुड़ा वाइस चांसलर है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक व्यक्ति है, आपका असली दुश्मन आरएसएस है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सोचा, इडियट भी है और स्टूडेंट भी है। उससे पूछा कि ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है- अंध भक्त। ये तीन कैटेगरी है। छात्र जो है, वह शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे है। स्टूडेंट आठ-10 घंटे पढ़ते है, एजुकेशन महंगी है।

पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास

7 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना

नई दिल्ली । लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए है। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं

राज्यसभा में वंदेमातरम से जुड़ा संशोधित बिल पास

राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल पास हो गया। अब जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। नए कानून में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों के प्रावधान है।

सीजेपी के वादे पूरे करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा- फारूक अब्दुल्ला

जम्मू । नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) से किए गए वादे पूरे करने चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, ''अगर वे (सरकार) अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, और प्राथमिकी वापस नहीं लेते है या उन लोगों को परेशान करना बंद नहीं करते हैं जिन्होंने वहां (जंतर-मंतर) भोजन और पानी मुहैया कराया, तो यह आंदोलन और भी बढ़ेगा तथा बदलाव लाएगा।'' बिहार में प्रदर्शनकारियों पर एक पुलिसकर्मी द्वारा एके47 से गोली चलाने के सवाल पर नेकां प्रमुख ने कहा, ''हर कोई यह जानता है, और आपने सुना होगा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष (नेहा) ने क्या कहा है। यह नहीं रुकेगा। बच्चे इसके खिलाफ खड़े हो गए है... वे इसे आगे ले जाएंगे।'' पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा पांच अगस्त (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वर्षगांठ) पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर, अब्दुल्ला ने कहा, ''वह जो चाहें वह कर सकती हैं''।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि कश्मीर में पिछले छह वर्षों में बनाए गए 5,000 होटलों में से 90 प्रतिशत ''अवैध'' हैं, अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल को आभारी होना चाहिए कि होटल घाटी में आने वाले पर्यटकों को समायोजित करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, ''आभारी रहें कि होटलों का निर्माण किया गया। पर्यटक यहां आते है। वे कहां रहेंगे? मैंने वो समय भी देखा है जब वो (पर्यटक) टैक्सी में सोते थे, कार में सोते थे। वे सड़क पर सोते थे। कोई जगह नहीं थी। ईश्वर का शुक्र है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हुए और उन्होंने सरकारी नौकरियों की आस नहीं देखी।''

ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्रीः अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमले किए, 20 की मौत

वॉशिंगटन डीसी । ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है जबकि 32 घायल हुए है। अमेरिकी सेना के मुताबिक, इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थीं, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया।

'बीजेपी जॉइन करो, नहीं तो माता-पिता को नुकसान होगा', दीपके की मां का दावा

नेशनल डेस्क । कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने बुधवार को दावा किया कि जब उनके बेटे ने जैसे ही व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया, उसे एक वीडियो के जरिए धमकी दी गई। अनीता ने कहा कि इस वीडियो में उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए कहा गया और ऐसा न करने पर माता-पिता को मुश्किल में डालने की चेतावनी दी गई।

उन्होंने बताया कि इस धमकी के कारण उसके माता-पिता को छत्रपति संभाजीनगर छोड़ना पड़ा और कोंकण इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर दो हफ्ते तक रहना पड़ा। अभिजीत की मां और पिता भगवान दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में एक मराठी न्यूज चैनल से बात की। यह बातचीत उनके बेटे के घर लौटने से पहले हुई, जिन्होंने नई दिल्ली में अलग-अलग परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर 36 दिनों तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी मां ने दावा किया, ''अभिजीत को धमकियां मिली थीं, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। उसने मुझे एक वीडियो के बारे में बताया और सलाह दी कि मैं उसे न देखूं। वीडियो में उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह भाजपा में शामिल नहीं हुआ, तो उसके माता-पिता के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।'' उन्होंने बताया कि बाद में अभिजीत ने माता-पिता से कुछ दिनों तक घर से दूर रहने को कहा। उनकी मां ने कहा, ''अभिजीत ने मुझसे कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरता नहीं है, लेकिन उसने हमसे कहा कि चूंकि हमें ऐसी धमकियों की आदत नहीं है, इसलिए हमें घर से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हमने घर से बाहर जाने का फैसला किया और कोंकण में एक रिश्तेदार के घर चले गए, जहां हम 16 दिनों तक रहे।'' उन्होंने कहा, ''उसे चिंता थी क्योंकि उस समय वह हमारे साथ नहीं था और उसके पिता को निम्न रक्तचाप की समस्या है।'' उनके पिता ने कहा कि समाज सेवा करते समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग

कोलकता । तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार (29 जुलाई 2026) को इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने विरोधी गुटों की तरफ से किए गए दावों पर जल्द से जल्द जांच करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को दो बार समय बढ़ाने की सुविधा दी गई. इसके बाद भी वह जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उनके गुट ने आयोग की तरफ से 6 जुलाई की समय सीमा के भीतर अपनी राय दे दी थी. विरोधी गुट को पहले 10 फिर 25 जुलाई तक का समय दिया गया था. ममता ने कहा, 'दो बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसलिए माना जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 के हमारे पत्र में बताई गई सारी बातें और बयान मान लिए गए हैं. उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है. उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं है. बनर्जी ने कहा है कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है. जबकि उनके गुट ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है.

झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहे ऋतब्रत बनर्जी गुटः ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके द्वारा समय बढ़ाए जाने के कारण ऋतब्रत बनर्जी और अन्य लोग अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इनके आरोपों में कोई दम नहीं है. इनका हमने पूरीत मजबूती से खंडन किया है. दोनों पक्षों के लिए समान अवसर होने चाहिए, 25 जुलाई के बाद विरोधी गुट को और समय देना गलत होगा. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि पश्चिम बंगाल में इस मामले में गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं. इसलिए अनुरोध है कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. उन्हें अपनी राय देने के लिए और समय न दें. 2 जुलाई को आयोग के पत्र में भी समय मांगा गया था. इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि न्याय भरोसे पर आधारित होना चाहिए. अगर 25 जुलाई 2026 के बाद और समय दिया जाता है, तो यह भरोसा डगमगा जाएगा. दरअसल, पूरा मामला 2 जुलाई को चुनाव आयोग के पास पूरा मामला पहुंचा. जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क किया. इसमें उन्होंने खुद को असली AITC बताया और संगठनात्मक बदलावों को मान्यता देने की मांग की. इसके बाद चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी दोनों को पत्र लिखकर विरोधी दावों पर उनकी राय मांगी. 6 जुलाई को शाम 5.30 बजे तक जवाब देने को कहा गया. जहां बनर्जी के नेतृत्व गुट ने सही समय पर जवाब दे दिया. वहीं ऋतब्रत बनर्जी के गुट ने और समय मांगा और उन्हें 10 जुलाई और बाद में 25 जुलाई तक समय दिया गया. इसी महीने की शुरुआत में विरोधी गुट के दावे को ममता बनर्जी गुट ने खारिज कर दिया था. ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि आखिरी संगठनात्मक चुनाव 2022 में हुए थे. तर्क दिया कि विरोधी गुट का यह दावा कमेटियां 2025 में खत्म हो गई, तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत है.

> ममता ने कहा, 'दो बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसलिए माना जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 के हमारे पत्र में बताई गई सारी बातें और बयान मान लिए गए है. उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है

राजा रघुवंशी हत्याकांडः सोनम ने किया आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत; न्यायिक हिरासत में भेजी गई

शिलांग । राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी ने मंगलवार को मेघालय की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को मेघालय की एक ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम को दी गई जमानत रद्द करते हुए उसे तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। सोनम को पिछले वर्ष जून में अपने कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजा और सोनम 23 मई 2025 को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में हनीमून मनाने गए थे, जहां दोनों लापता हो गए थे। बाद में 2 जून 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से हनीमून के दौरान राजा की हत्या की साजिश रची .

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।